पंजीकृत फर्जी फर्मों पर करें कार्रवाई : सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेल कंपनियों एवं पंजीकृत फर्जी फर्मों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। चेतावनी दी कि व्यापारियों की सुविधाओं में सेंध लगाने का प्रयास करने वाले राज्य कर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अक्षम्य अपराध है। साथ ही निर्देश दिए कि कम राजस्व संग्रह वाले क्षेत्रों की विशेष रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी जाए।

शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के बाद निर्देश दिए कि कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाई जाए। कर चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है और इससे राज्य की विकास योजनाओं तथा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां से अपेक्षाकृत अधिक कर प्राप्त होना स्वाभाविक है। अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे जोन जहां कर संग्रह औसत से कम है, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके। वहीं स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों की विभागीय स्तर पर गहन जांच की जाए। यदि अनियमितता मिले तो पंजीकरण निरस्त कर एफआइआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी नई पंजीकृत फर्मों के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न हो कि कुछ फर्जी कंपनियां ईमानदार करदाताओं के अधिकारों को बाधित करें। इसलिए सभी नई पंजीकृत फर्मों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए, जिससे वास्तविक फर्म ईमानदारी से अपना कार्य कर सकें।

राज्य कर अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,75,725 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल-मई माह में अब तक 18,161.59 करोड़ रुपये का जीएसटी और वैट संग्रहित किया जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, अयोध्या, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, झांसी और सहारनपुर सहित 14 जोन में 60 प्रतिशत या उससे अधिक लक्ष्य पूर्ति को सराहनीय बताया। वहीं वाराणसी जोन प्रथम, प्रयागराज, कानपुर-द्वितीय, इटावा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे जोन में 50 प्रतिशत से कम संग्रह को असंतोषजनक बताते हुए तत्काल व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया।

'पिछली सरकारें करती थीं मक्कारी, हम बढ़ा रहे मक्का उत्पादन'

जागरण संवाददाता, औरैया : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें महापुरुषों का अपमान और जनता से मक्कारी करती थीं। भाजपा सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाने के साथ महापुरुषों का सम्मान भी करती है।

केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विज्ञानियों, कृषि विवि के प्राध्यापकों और कृषि विज्ञान केंद्रों के विज्ञानियों को पहली बार किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की प्रक्रिया, बीज से बाजार तक किसान के हित को सर्वोपरि मान चलाए गए अभियान का हिस्सा है। किसान पहले एक या दो फसल तक सीमित थे, आज वे तीसरी फसल (मक्का) का पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन करके मुनाफा कमा रहे हैं। यही किसान के परिवर्तन का आधार है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव, कन्नौज और औरैया के साथ कानपुर का हवाई सर्वे करके मक्का की फसल देखी

अजीतमल में सम्मेलन को संबोधित करते सीएम योगी ● जागरण

मुख्यमंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 के तहत रविवार को अजीतमल के जनता डिग्री कालेज में मक्का किसानों से संवाद किया। मक्का की रिकार्ड पैदावार पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औरैया में जल्द ही मक्का खरीद के लिए सरकारी क्रय केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाएगा। राज्य सरकार ने खाली खेतों में जायद की फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया। 2017 से अब तक 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने उन्नाव, कन्नौज, कानपुर के साथ औरैया जिले की मक्का की फसल का हवाई सर्वे किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य मौजूद रहीं।